

The 16th October, 1984

No. 11912.—Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. 11073/2-L, dated 20th September, 1984 issued under section 6(17) of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed at the expense of the Government of Haryana for a public purpose namely, additional land proposed to be acquired for constructing Kamania minor from Kilometre 2,400 to Kilometre 4,400 off taking from Kilometre 11.003 left Shahbazpur Distributary in village Kamania, Nangal Pipa, Chhapra Bibipur and Avtri in tehsil Narnaul District Mahendragarh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 the Governor of Haryana, hereby directs the Land Acquisition Collector, Public Works Department Irrigation Branch, Narnaul to take order for the acquisition of the land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification.

SPECIFICATION

Serial No.	District	Tehsil	Name of village	Area in acres	Direction
1	Mahendragarh	Narnaul	Kamania	0.944	And generally lying in the direction from North-West to South-East and North-East to South-West as demarcated at site as shown on the Index Plan
2	Do	Do	Nangal-Pipa	9.313	
3	Do	Do	Chhapra-Bibipur	4.771	
4	Do	Do	Avtri	1.347	
Total				16.375	

By order Governor of the Haryana.

S. C. AHUJA,

Superintending Engineer,
Jawahar Lal Nehru Canal Circle No. II,
Rohtak.

श्रम विभाग

दिनांक 20 सितम्बर, 1984

सं० अ० वि०/सोनीपत/203-84/36039.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० सोनीपत आयरन एण्ड स्टील रोलिंग मिल इण्डस्ट्रीयल ऐरिया सोनीपत, के श्रमिक श्री सत्य नारायण तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम 70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए.एस.ओ. (ई) 70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद ग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री सत्य नारायण की सेवाओं का समाप्त न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

वी० पी० सहगल,

संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,

श्रम विभाग ।